vkj- ,u- vkbZ- u- UPHIN/2010/32566 Mkd- iathdj.k la[;k& SSP/LW/NP-311

अद्भुत समाचार

निष्पक्ष एवं निर्भीक हिन्दी साप्ताहिक
हर ख़बर पर पैनी नज़र

o"kZ % 11 vad % 39 y[kuÅ] xq:okj 21 tuojh ls 27 tuojh] 2021 rd i"B&8 ewY; % ,d :i;k

ट्रैक्टर रैली में अदालत का दखल नहीं

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली पर अब सरकार और दिल्ली पुलिस को ही फैसला करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दूसरी बार इस मामले में विचार करने और कोई भी आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। इससे पहले सोमवार को भी चीफ जस्टिस एसए बोबड़े की बेंच ने कहा था कि २६ जनवरी को प्रस्ताविक ट्रैक्टर रैली निकाली जाए या नहीं यह कानून–व्यवस्था का मामला है और इस पर पुलिस को ही फैसला करना चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा कर इस रैली पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। इस पर बुधवार को सुनवाई हुई, जिसमें चीफ जस्टिस एसए बोबडे की बेंच ने कहा– किसानों की ट्रैक्टर रैली या किसी प्रदर्शन के खिलाफ सरकार की याचिका पर कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। हम पहले ही कह चुके हैं कि इस बारे में पुलिस को फैसला लेने दें। अदालत ने सरकार से कहा– आप याचिका वापस ले सकते हैं। इस मामले में आप अथ रिटी हैं, आप ही डील कीजिए। यह ऐसा मामला नहीं कि कोर्ट आदेश जारी करे। अदालत की इस टिप्पणी के बाद

सरकार ने अपनी याचिका वापस ले ली। किसानों के वकील प्रशांत भूषण ने अदालत में कहा कि किसान बाहरी रिंग रोड पर गणतंत्र दिवस मनाना चाहते हैं। इस दौरान शांति भंग की कोशिश नहीं की जाएगी। इस मामले में पुलिस का कहना था कि कोई भी रैली या ऐसा विरोध जो गणतंत्र दिवस समारोह में खलल डालने की कोशिश करता है, वह देश को शर्मिंदा करने वाला होगा। पुलिस ने कहा कि इससे दुनिया भर में देश की बदनामी होगी। कानून–व्यवस्था खराब होने की स्थिति बन सकती है। इस बीच किसान नेताओं ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की पुलिस के साथ बुधवार को लगातार दूसरे दिन मीटिंग की। इससे पहले मंगलवार की मीटिंग में पुलिस ने किसान नेताओं से ट्रैक्टर रैली नहीं निकालने की अपील की। लेकिन बैठक के बाद किसान नेता दर्शन पाल ने कहा– ट्रैक्टर रैली तो निकालेंगे, लेकिन पुलिस को भरोसा दिया है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा। किसानों का कहना है कि २६ जनवरी को ट्रैक्टर रैली दिल्ली के बाहरी रिंग रोड पर तिरंगे के साथ निकाली जाएगी। गणतंत्र दिवस समारोह में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। दूसरी ओर पुलिस ने रैली पर रोक लगाने के मकसद से अलग–अलग रिपोर्ट्स का हवाला देकर कहा है कि कई किसान गणतंत्र दिवस की परेड में खलल डालने के लिए लाल किले तक पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं।

मोदी सरकार ने बजट से पहले ३० जनवरी को बुलाई सर्वदलीय बैठक

नई दिल्ली। एक फरवरी को पेश होने वाले बजट से पहले मोदी सरकार सभी दलों से विचार– विमर्श करेगी। केंद्र सरकार ने ३० जनवरी को वीडियो कांफ्रेंसिंग से होने वाली सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों के दोनों सदनों के नेताओं को आमंत्रित किया है। कोरोना से जुड़ी सभी सतर्कता के बीच बजट सत्र दो टुकड़ों में आयोजित होगा। संसद के बजट सत्र का पहला चरण २६ जनवरी से १५ फरवरी तक चलेगा तो दूसरा भाग आठ मार्च से आठ अप्रैल तक आयोजित होगा। सूत्रों का कहना है कि इसी दिन एनडीए की भी बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, राज्यसभा में नेता थावरचंद गहलोत, उपनेता पीयूष गोयल, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, अर्जुन राम मेघवाल और वी. मुरलीधरन सरकार की तरफ से भाग लेंगे। इस बैठक में सभी राजनीतिक दलों के दोनों सदनों के नेता भी हिस्सा लेंगे।

साढ़े ११ बजे से बुलाई गई यह बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। २६ जनवरी से प्रारंभ होने जा रहे बजट सत्र में फिर से एक घंटे का प्रश्न काल बहाल कर दिया गया है। जबकि कोरोना काल में सितंबर में हुए मानसून सत्र के दौरान प्रश्नकाल को स्थगित कर दिया गया था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मंगलवार को एक प्रेस कांफ्रेंस में बताया था कि बजट सत्र के दौरान संसद आने वाले सांसदों का कोरोना टेस्ट अनिवार्य होगा।

वेतन एक मौलिक अधिकार है : दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली। कर्मचारियों को वेतन और पेंशन का भुगतान न करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने आज नगर निगमों की जमकर खिंचाई की। कोर्ट ने कहा कि धन की कमी एक बहाना नहीं हो सकता और वेतन पाने का अधिकार भारत के संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है। जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की खंडपीठ, दिल्ली नगर निगमों, विशेष रूप से उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) और पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) के कर्मचारियों को वेतन और पेंशन का भुगतान नहीं करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने कहा, समय पर वेतन का भुगतान न किए जाने का कारण धन की कमी बताया गया है। ये एक बहाना नहीं हो सकता क्योंकि वेतन और पेंशन लोगों का मौलिक अधिकार है। अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद २१ के तहत वेतन का भुगतान नहीं करने का सीधा असर लोगों के जीवन की गुणवत्ता पर पड़ेगा। अदालत ने आगे कहा कि यह बहुत जरूरी है कि निगमों के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वेतन और पेंशन का भुगतान किया जाय, जिसमें डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी शामिल हैं, और जो महामारी के समय में भी अपनी सेवाएं दे रहे थे। बेंच ने आगे कहा कि पैसे की कमी बहाना

नहीं हो सकती और न ही इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। वेतन और पेंशन के भुगतान को अन्य खचरें से ज्यादा प्राथमिकता देनी होगी। अगली सुनवाई २१ जनवरी तक स्थगित करते हुए कोर्ट ने कहा, इसलिए, हम नगर निगमों को निर्देश देते हैं कि वो विभिन्न मदों में किए जाने वाले खर्च का ब्योरा दे। कर्मचारियों के लिए भत्ते की राशि विशिष्ट मद में स्पष्ट रूप से प्रकट किया जाना चाहिए। नगर निगमों के कर्मचारी अपनी तनख्वाह न मिलने को लेकर ७ जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं।

जागरूकता से रोकी जा सकती हैं सड़क दुर्घटनाएं : योगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में हर दिन सड़क दुर्घटनाओं में लगभग ६५ मौतें होती हैं। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा कर इन दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सरकारी आवास पर सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर दिन सड़क दुर्घटनाओं में लगभग ६५ मौतें होती हैं। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा कर इन दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। प्रदेश सरकार ने करीब साढे तीन वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं के कारकों को खत्म करने के तमाम प्रयास हो रहे हैं। अभी भी इसमें बहुत कुछ किया जाना है। सड़क सुरक्षा माह के दौरान प्रदेश भर में जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जाएंगे। योगी ने कहा कि गाड़ी चलाने योग्य लाइसेंस देखने की जिम्मेदारी परिवहन विभाग की है। एक माह तक चलने वाला ये अभियान सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के संबंध में काफी मदद करेगा। इस कार्यक्रम के लिए पूरे प्रदेश में हर जिले में जिलाधिकारी इसके नोडल अधिकारी होंगे। स्कूल क लेज में जाकर

यातायात नियमों की जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतें रोकी जा सकती हैं, बस थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। २० फरवरी तक हर जिले में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसमे परिवहन, गृह, स्वास्थ्य विभागों के साथ ही स्कूल कॉलेज शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण से जुड़ी संस्थाएं हैं चाहे लोक निर्माण विभाग हो या राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सभी को सड़क दुर्घटनाओं के कारण चिह्नित करने की आवश्यकता है। इस अवसर पर उन्होंने परिवहन विभाग की ५५.७० करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा कि हाई स्पीड भी सड़क दुर्घटना का कारण बनती है। इसी तरह हाइवे पर अवैध अवरोध भी दुर्घटना का कारण है। इसके अलावा शराब पीकर गाड़ी चलाना या वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना आदि छोटे–छोटे कई कारण हैं, जिससे होने वाली दुर्घटनाओं से परिवार व समाज को बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। केंद्र सरकार दुर्घटनाएं रोकने के लिए काफी सक्रिय है। उच्चतम न्यायालय भी सड़क दुर्घटनाओं के लिए काफी जागरूक है। अक्सर सवाल पूछते हैं कि क्या उपाय कर रहे हैं।

सम्पादकीय

लोकतंत्र में स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पैसे का बोलबाला

महाराष्ट्र से आई खबर हैरतअंगेज तो नहीं थी, लेकिन उससे अपने लोकतंत्र की स्थिति पर विचार करने का एक मौका जरूरत मिलता है। हैरतअंगेज इसलिए नहीं थी, क्योंकि अपने लोकतंत्र में स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पैसे का बोलबाला है, यह आम जानकारी है। लेकिन जब हालात ऐसे हों, तो फिर यह जरूरत सोचना पड़ता है कि आखिर हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने की बात कहकर गर्व क्यों करते हैं? खबर यह आई कि निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र के नासिक और नंदूरबार जिलों के दो गांवों में पंचायत चुनाव रद्द कर दिया है। आयोग को पंचायत सीटों की नीलामी की शिकायत और वीडियो मिले थे। उसके बाद १५ जनवरी को होने वाले चुनाव को रद्द कर दिया गया। मतदाताओं को पैसा बांटने के आरोप में पहले विधान सभा की सीट का चुनाव भी रद्द हुआ है। लेकिन इस बार खबर सीट की नीलामी की है। महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग को नासिक के उमराने और नंदूरबार के खोंडामली की ग्राम पंचायतों के सरपंच पद और पंचायत सदस्यों के चुनाव के लिए बोली लगने की शिकायतें मिली थीं। नासिक के उमराने गांव में बोली दो करोड़ रुपये तक लगाई गई। नंदूरबार के खोंडामली में नीलामी की रकम ४२ लाख रुपये तक पहुंची। गांव की आबादी के हिसाब से ग्राम पंचायत में ६ से लेकर १८ सदस्य होते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के आधिकारिक बयान के मुताबिक आयोग ने जिला अधि ाकारियों, चुनाव पर्यवेक्षकों और तहसीलदारों से मिली रिपोर्ट का अध्ययन करने और दस्तावेजों और वीडियो देखने के बाद चुनाव प्रक्रिया को रद्द करने का फैसला किया। यह बात जरूर चौंकाने वाली है नीलामी सरेआम हो रही थी। बोली की पूरी प्रक्रिया को किसी भी तरह से गुप्त नहीं रखा गया। नीलामी प्रक्रिया की रिक डिंग का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला अधिकारियों और पुलिस को निर्देश दिया है कि वे भारतीय दंड संहिता की धारा १७१ (सी) के मुताबिक संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। आरोप है कि कुछ उम्मीदवारों ने कथित रूप से वादा किया था कि अगर वे सरपंच पद के लिए निर्विरोध चुने जाते हैं, तो वे बड़े पैमाने पर गांव के विकास के लिए अपना धन खर्च करेंगे। हो सकता है ये नया वलन धीरे– धीरे यह विधानसभा और लोकसभा स्तर पर भी होने लगे...??

यूपी दिवस में जन जन को भागीदार बनाएगी योगी सरकार

लखनऊ। योगी सरकार प्रदेश के लोगों को मिट्टी के सम्मान और स्वाभिमान से जोड़ने के लिए एक अनूठी मुहिम शुरू करने जा रही है। २४ जनवरी को होने वाले उत्तर प्रदेश दिवस के जरिये राज्य सरकार प्रदेश वासियों में अपनी मिट्टी के प्रति जुड़ाव को और मजबूत करेगी। योगी सरकार यूपी दिवस के कार्यक्रमों में जन जन को भागीदार बनाएगी। राज्य की सत्ता संभालने के बाद यूपी दिवस की शुरूआत कर प्रदेश के लोगों को अपनी मिट्टी पर गौरव का अनुभव कराने वाली योगी सरकार इस बार हर जिले में उत्तर प्रदेश दिवस मनाने जा रही है। प्रदेश के छोटे बड़े सभी जिलों में यूपी दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में सरकार और स्थानीय प्रशासन के साथ ही आम लोग भी सहभागिता कर सकेंगे। यह पहली बार होगा

जब राजधानी लखनऊ के अतिरिक्त जिलों में भी यूपी दिवस के कार्यक्रम आयोजित होंगे। तीन दिन तक चलने वाले यूपी दिवस समारोह के कार्यक्रमों के तहत जिलों में नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विचार गोष्ठी जैसे कार्यक्रम आयोजित कर उत्तर प्रदेश के गौरवपूर्ण इतिहास के साथ ही विकास गाथा को भी प्रस्तुत किया जाएगा। योगी सरकार ने यूपी दिवस के कार्यक्रमों के लिए सभी जिलों के प्रशासनिक और पुलिस अफसरों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि २४ जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के शिल्पग्राम में उत्तर प्रदेश दिवस समारोह का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री २५ जनवरी को नोएडा में उत्तर प्रदेश दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जिलों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में जिला अधिकारी समेत अन्य विभागों के अफसर और कर्मचारी सहभागी बनेंगे।

अनाज भंडारण के लिए 5 हजार गोदाम बनाने जा रही योगी सरकार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए अनाज भंडारण के लिए प्रदेश भर

में गोदाम बनाने जा रही है। पहले चरण में ५ हजार भंडारण गोदाम बनाने की योजना पर केंद्र ने मुहर लगा दी है। भूमि के चयन के साथ ही राज्य सरकार गांवों में अनाज भंडारण गोदामों का निर्माण शुरू करेगी। किसानों को अपना अनाज रखने के लिए दूर नहीं जाना होगा। फसल खराब होने की मजबूरी में उसे कम कीमत में भी नहीं बेचना पड़ेगा। अनाज भंडारण गोदाम बनाने की योजना पर करीब २५०० करोड़ रुपये खर्च होंगे। इन सभी गोदामों की कुल भंडारण क्षमता करीब ८.६० लाख मीट्रिक टन होगी। इन गोदामों में किसानों के अनाज के साथ ही सरकार भी स्थानीय स्तर पर खरीदे गए अनाज का भंडारण भी कर सकेगी। अनाज भंडारण गोदाम की योजना को योगी सरकार गांवों में रोजगार से भी जोड़ने जा रही है। भंडारण निगमों में स्थानीय लोगों को केयर टेकर, संचालक और बाबू के पदों पर संविदा और स्थाई दोनों तरह से रोजगार के अवसर दिए जाएंगे।

किसानों को उद्योगपति बनने के गुर सिखाएगी यूपी सरकार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को खेत से लेकर खलिहान तक और बीज से लेकर बाजार तक आत्मनिर्भर बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। किसानों को सिखाया जाएगा कि वह किस प्रकार से उद्यमी बन सकते हैं और अपनी उपज को उत्पाद बनाकर कैसे बाजार में बेच सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर फार्मर प्रोड्यूसर आर्गनाईजेशन (एफपीओ) की क्रियान्वयन नियमावली जारी कर दी गई है। सरकार की पहल पर प्रदेश का यह पहला मौका है, जब १७ विभाग मिशन मोड में एक साथ किसानों के लिए कार्य करेंगे। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डालर के रूप में स्थापित करने में 'उत्तर प्रदेश कृषक उत्पादक संगठन नीति २०२०' महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसकी मूल अवधारणा प्रदेश के हर किसान परिवार को उद्यमी के रूप में संगठित कर खेती बाड़ी में स्थापित करते हुए पूरा आत्मनिर्भर बनाना है। नीति में एफपीओ के गठन के लिए कम से कम १० किसान अलग–अलग परिवारों के होने चाहिए। इसके बाद रजिस्ट्रेशन और उससे संबंधित पहले साल की विधिक कार्यवाही पूरी करने के लिए करीब ३६,५०० रुपए का खर्च संभावित है। एफपीओ के रजिस्ट्रेशन के लिए राज्य स्तर पर कंपनी सेक्रेटरी का एक पैनल बनाया जाएगा, जो एफपीओ के प्रशासनिक, वित्तीय, वैधानिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन में आ रही कठिनाईयों को दूर करने में सहयोग करेगा। इसमें चयनित कंपनी सेक्रेटरी के विभिन्न कार्यों के लिए फीस निर्धारित की जाएगी, जिनके माध्यम से इच्छुक एफपीओ अपना पंजीकरण करा सकेंगे। एफपीओ को क्रियाशील बनाने और शेयर होल्डर्स की संख्या बढ़ाने में राज्यस्तरीय परियोजना प्रबंधन ईकाई की ओर से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी। इसके लिए विभिन्न विशेषज्ञों की भर्ती प्रक्रिया, योग्यता, उनके कर्तव्य और उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। इन विशेषज्ञों की ओर से

विभिन्न विभागों से समन्वय कर उनके द्वारा संचालित परियोजनाओं से कन्वर्जेंस सपोर्ट दिया जाएगा। इससे एफपीओ के व्यवसायिक कार्य शुरू हो जाएंगे। नई नीति में राज्य स्तरीय परियोजना प्रबंधन ईकाई की ओर से सफल एफपीओ को राष्ट्रीय स्तर पर भ्रमण भी कराया जाएगा। इसी तरह अंतर जनपदीय भ्रमण साल में दो बार, अंतरराज्यीय भ्रमण साल में एक बार कराया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में सहभागिता आध ाार पर भ्रमण कार्यक्रमों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा मानिटरिंग रिपोर्ट के आधार पर सफल एफपीओ को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार भी दिए जाएंगे। एफपीओ को कन्वर्जेंस सहायता देने वाले १७ विभागों को चिह्नित किया गया है। इसमें कृषि विभाग, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, पशुधन विभाग, ग्राम्य विकास समेत अन्य विभागों को शामिल किया गया है। नीति के मुताबिक एफपीओ को पांच लाख रुपए तक के लोन पर ब्याज दर में से चार प्रतिशत का अनुदान देने की भी योजना है। एफपीओ से जुड़ी हर जानकारी के लिए एक पोर्टल भी बनाया जाएगा, जिस पर एफपीओ से जुड़ी सभी प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध रहेंगीं। प्रदेश में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र में बढ़िया काम करने वाले अग्रणी किसानों की एक एफपीओ सलाहकार समिति भी बनाई जाएगी। इसमें धान, दलहन, तिलहन, सब्जी, फल, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य, रेशम, पुष्पोत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, विपणन आदि क्षेत्र के अग्रणी किसानों को सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा। एफपीओ के सफल क्रियान्वयन के लिए किसानों से लेकर अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए राज्य स्तरीय ईकाईयों की ओर से एक प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार होगा। जिसके क्रम में कृषि विभाग के मंडल, जिले और खंड विकास स्तरीय अधिकारियों का अलग अलग बैचों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य स्तर पर ेषि उत्पादन आयुक्त को अध्यक्ष, मंडल स्तर पर कमिश्नर को अध्यक्ष और जिले स्तर पर डीएम को अध्यक्ष बनाया गया है।

उत्तर प्रदेश में नड्डा देंगे जीत का मंत्र, चुनावी मोड में जुटी भाजपा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधान परिषद और पंचायत चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अब २०२२ के विधानसभा चुनाव में उतरने जा रही है। उसके ठीक पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्

यक्ष जेपी नड्डा २१ और २२ जनवरी को लखनऊ आ रहे है। इस दौरान वह सरकार और संगठन दोंनों की थाह लेंगे। पार्टी को जीत का मंत्र भी बताएंगे। नड्डा गुरुवार को पहली बार लखनऊ दौरे पर आ रहे हैं। अलग–अलग राज्यों में प्रवास कर रहे नड्डा का उत्तर प्रदेश में दो दिनी प्रवास काफी अहम है, क्योंकि इन दिनों संगठन से लेकर सरकार में तमाम पदों पर नई जिम्मेदारियों के कयास चल रहे हैं। नड्डा संगठन पदाधिकारियों के साथ योगी सरकार के मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा भी करेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के साथ वर्ष २०२२ के विधानसभा चुनाव की तैयारियों की जानकारी लेंगे। नड्डा सरकार और संगठन के साथ अलग–अलग बैठकें कर आगामी चुनावों को लेकर रणनीति पर चर्चा करेंगे। इसे देखते हुए यहां संगठन भी अपना होमवर्क गंभीरता से कर रहा है। दौरे की तैयारियों को लेकर मंगलवार को प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने वार्ड और मंडल के पदाधिकारियों से लेकर अवध व कानपुर क्षेत्र के पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों के साथ अलग–अलग बैठकें कीं। सभी को नड्डा के प्रवास कार्यक्रम की रूपरेखा समझाई गई। भाजपा के सूत्र बताते है कि जेपी नड्डा के आने के बाद यह तय हो जाएगा कि यूपी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होगा या नहीं। उनके पास सरकार के कुछ मंत्रियों के कामकाज को लेकर अच्छा फीडबैक नहीं है। वह न केवल मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा करेंगे बल्कि उनको बुलाकर बात भी करेंगे। उनसे बात करने के बाद ही वह मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन महामंत्री सुनील बंसल के साथ बैठक कर इस पर मंथन करेंगे। रिटायर्ड आईएएस ए.के. शर्मा के आने और विधानपरिषद का नामांकन करने के बाद उनका क्या भविष्य होगा। इसे लेकर भी चर्चा की जाएगी। शर्मा की प्रदेश में भूमिका भी नड्डा के आगमन पर ही स्पष्ट होगी। माना जा रहा है कि शर्मा के अनुभव का लाभ प्रशासनिक कार्यकुशलता व दक्षता बढ़ाने में लिया जाएगा ताकि विधायकों के एक खेमे में अधिकारियों के रवैये को लेकर बढ़ता असंतोष काबू किया जा सके। ऐसे में मंत्रिमंडल से कई मंत्रियों की छुट्टी होने की संभावनाएं भी जतायी जा रही हैं। पंचायत चुनाव से पूर्व किसान आंदोलन से गांवों में आक्रोश को नहीं बढने देने पर भी विचार होगा।

विवादित बयान के मामले में फंसे सोमनाथ भारती जेल से रिहा

सुल्तानपुर। विवादित बयान मामले में फंसे आम आदमी पार्टी के विधायक व दिल्ली के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती को मंगलवार को जेल से रिहा कर दिया गया। रिहाई को लेकर आप कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार किया। विधायक सीधे दिल्ली रवाना हुए है। सोमवार की

देर शाम रिहाई का आदेश जेल में पहुंचा था। सदर कोतवाली में दर्ज कराए गए आपराधिक मामले में एमपी– एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार बरनवाल ने १६ जनवरी को जमानत अर्जी सुनवाई के बाद स्वीकार करते हुए आरोपी विधायक को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। गौरतलब है कि मामले की रिपोर्ट सदर कोतवाल अतुल सिंह ने ११ जनवरी को दर्ज कराई थी। विधायक को कोर्ट ने १५ जनवरी को न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए जेल भेजा था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने विधायक को ५० हजार के व्यक्तिगत बंधपत्र व इतनी ही धनराशि की दो जमानत दाखिल करने पर सशर्त जमानत दे दी थी। विधायक के अधिवक्ता सुरेंद्र बहादुर सिंह भदौरिया ने बताया कि सोमवार को जमानतदारों की ओर से दाखिल जमानत प्रपत्रों की सत्यापन रिपोर्ट आने के बाद विधायक की रिहाई का आदेश कोर्ट की ओर से जिला जेल सुल्तानपुर भेजा गया। बताते चलें कि आप विधायक पर बीते दस जनवरी को अमेठी जिले के जगदीशपुर थाने में यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था।

अयोध्या में राम मंदिर के नींव का निर्माण शुरू

अयोध्या। अयोध्या के राम जन्मभूमि में रामलला के गर्भ गृह स्थल पर आज से नींव के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया । वैदिक आचार्य द्वारा कार्य प्रारम्भ से पूर्व बताया कि बीते पांच अगस्त को प्रध ाानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूमि पूजन किए जाने के बाद से ही प्रतिदिन गर्भ गृह स्थल पर हवन व दीप जलाने का क्रम चलता आ रहा है।

पूजन–अर्चन किया गया। अभी तक रामलला के गर्भगृह स्थल के चारों तरफ का मलबा हटाया जा रहा था। गुरुवार से मुख्य गर्भगृह स्थल पर नींव के निर्माण का काम प्रारम्भ कर दिया गया है। राम जन्मभूमि के पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि रामलला के गर्भगृह स्थल के पास भी कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इससे पूर्व वहां पूजन–अर्चन किया गया। उन्होंने मकर संक्रांति के साथ सूर्य के उत्तरायण होने के बाद रामजन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के निर्देश के बाद कार्यदायी संस्था लार्सन टूब्रो ने नींव की खुदाई आज सुबह शुरू करा दी । काम को तेज करने के लिये एक अतिरिक्त पोकलैंड भी लगा दिया गया है ताकि काम जल्द से जल्द पूरा हो। इसबीच ट्रस्ट की मंदिर निर्माण समिति की दो दिवसीय बैठक आज शुरू हो रही है ।

डीआरएम ने किया लखनऊ सीतापुर रेलखंड का निरीक्षण

लखनऊ। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मण्डल की मण्डल रेल प्रबन्धक डा मोनिका अग्निहोत्री ने बुधवार को अपर मंडल रेल प्रबंधक परिचालन शिशिर सोमवंशी, के साथ लखनऊ सीतापुर–बुढ़वल रेलखण्ड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तप्पा खजुरिया, परसेन्डी, रमईपुर, बिसवॉं, सरैंया, महमूदाबाद(अवध), पैंतीपुर, तहसील फतेहपुर, सुढ़िया मऊ स्टेशनों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मण्डल रेल प्रबन्धक ने सीतापुर जंक्शन स्टेशन स्थित थॉमसन गंज गुड्स साइडिंग, स्टेशन यार्ड, पैनल रुम, क्रू लाबी, रनिंग रुम, सरकुलेटिंग एरिया, टिकट आरक्षण कार्यालय, खानपान स्टाल, यात्री प्रतीक्षालय, आरपीएफ पोस्ट को देखा। इसके पश्चात सीतापुर–तप्पा खजुरिया के मध्य कर्व संख्या ८, नॉन इंटरल क समपार संख्या ८७, इंटरल क समपार संख्या ८६ व तप्पा खजुरिया स्टेशन पर स्टेशन भवन,स्टेशन अधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया। इसके पश्चात तप्पा खजुरिया–परसेंडी के मध्य मेजर ब्रिज १२० तथा परसेंडी स्टेशन को देखा। इसके पश्चात परसेंडी रमईपुर के मध्य लो हाई शेल्टर संख्या ६७,रमईपुर स्टेशन पर स्टेशन अध ीक्षक कार्यालय, सरकुलेटिंग एरिया को देखा। बिसवां स्टेशन स्थित स्टेशन अधीक्षक कार्यालय, स्टेशन प्लेटफार्म, विद्युत टीएसएस

रेलवे कालोनी, सरकुलेटिंग एरिया को देखा। महमूदाबाद अवध व सरैंया स्टेशनो पर स्टेशन अधीक्षक कार्यालय, सरकुलेटिंग एरिया, पैंतीपुर तथा सुढ़ियामऊ स्टेशनों के स्टेशन अधीक्षक कार्यालय, सरकुलेटिंग एरिया व यात्री सुविध ााओं व विकास कार्यो का गहन निरीक्षण किया। डीआरएम ने बुढ़वल जंक्शन पर निरीक्षण के दौरान सरकुलेटिंग एरिया, स्टेशन अधीक्षक कार्यालय, टिकट आरक्षण कार्यालय, खानपान स्टाल, यात्री प्रतीक्षालय, आरपीएफ पोस्ट, आरक्षण कार्यालय व प्लेटफार्मो की सफाई व्यवस्था की जानकारी ली। संरक्षा व सुरक्षा के दृष्टिकोण से निरीक्षण के दौरान रेलपथ के रखरखाव व रेल संचालन में संरक्षा पर व्यक्तिगत रूचि लेने के लिये सम्बन्धित अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिये। इस अवसर पर लखनऊ मण्डल के वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक अम्बर प्रताप सिंह, वरिष्ठ मण्डल परिचालन प्रबंधक डा० हरीश रैड़तौलिया, वरिष्ठ मण्डल यॉत्रिक इंजीनियर (ओएण्डएफ) फणीद्र कुमार, वरिष्ठ मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियर एस.डी. पाठक, वरिष्ठ मण्डल संरक्षा अधि ाकारी अजय प्रताप सिंह, वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर द्वितीय मानसी मित्तल, वरिष्ठ मण्डल विद्युत इंजीनियर, धनन्जय मिश्रा, वरिष्ठ मण्डल विद्युत इंजीनियर टीआरडी धर्मेन्द्र यादव, सहायक मंडल सुरक्षा आयुक्त एस के वर्मन व अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

रोडवेज के चालकों ने दी चक्का जाम की धमकी

लखनऊ। रोडवेज बसों में सीटों की क्षमता के अनुसार ५० फीसदी यात्रियों का होना जरूरी है। इससे कम यात्री बस में होने पर चालक परिचालकों को प्रोत्साहन भत्ता नहीं मिलेगा। निगम प्रशासन के इस आदेश के विरोध में ड्राइवर कंडक्टरों ने चक्का जाम करने की धमकी दी है। लखनऊ क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक को सौंपे गए नोटिस में प्रति बस ५० फीसदी यात्री लोड फैक्टर की अनिवार्यता को समाप्त करने की मांग की गई है। संविदा चालक परिचालक कर्मचारी संघर्ष यूनियन के क्षेत्रीय अध्यक्ष कैशलेंद्र सिंह व क्षेत्रीय मंत्री आदर्श कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि यात्री लोड फैक्टर कम होने के नाम पर बस कंडक्टरों के वेतन से कटौती की जा रही है। जबकि यह नियम नियमित चालक परिचालकों पर नहीं लागू है। ऐसे में कोरोना काल और ठंडक में यात्रियों की कमी का खामियाजा संविदा के बस कंडक्टर क्यों भुगते? इन्हीं सवालों के साथ जिस दिन वेतन में कटौती होगी उसी दिन विरोध करते हुए कार्यबहिष्कार करने की चेतावनी दी है।

सरकार कानूनों पर अगले डेढ़ साल तक रोक को तैयार

नई दिल्ली। तीन केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले ५६ दिन से आंदोलन कर रहे किसान संगठनों को बड़ी सफलता मिली है। केंद्र सरकार उनकी मांग पर कुछ हद तक झुकने को तैयार हो गई है। सरकार तीन विवादित कृषि कानूनों पर अगले डेढ़ साल तक रोक लगाने के लिए तैयार है। पिछले साल बनाए गए तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों के साथ बुधवार को हुई १०वें दौर की वार्ता में सरकार ने यह प्रस्ताव किसानों के सामने रखा। इसके साथ ही सरकार ने यह भी कहा कि जब तक कानून पर अमल स्थगित रहेगा तब तक एक कमेटी बना कर विवाद के सारे मुद्दों को सुलझाया जाएगा। किसानों ने सरकार के इस प्रस्ताव को तुरंत नहीं स्वीकार किया है और यही कहा है कि उनकी मांग है कि कानूनों को निरस्त किया जाए, पर साथ ही किसानों ने कहा कि किसान संगठन इस पर विचार करेंगे। सरकार के साथ किसान संगठनों की अगली वार्ता २२ जनवरी को होगी। उससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े तमाम संगठन अपनी मीटिंग करके सरकार के नए प्रस्ताव पर विचार करेंगे और २२ जनवरी की बैठक में अपना जवाब सरकार के सामने रखेंगे। जानकार सूत्रों के मुताबिक आंदोलन कर रहे किसानों में से कई संगठन सरकार के इस प्रस्ताव पर सकारात्मक रूप से विचार के पक्ष में हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल केंद्रीय कृषि कानूनों पर रोक लगा रखी है। सरकार इसे आगे बढ़ाने को तैयार है। वह इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा भी देने को तैयार है। बहरहाल, इससे पहले

बुधवार को केंद्र सरकार और आंदोलन कर रहे किसान संगठनों की १०वें दौर की वार्ता विज्ञान भवन में हुई। इसमें केंद्र ने किसानों से कहा कि वह डेढ़ साल तक कृषि कानूनों को निलंबित करने को तैयार है। साथ ही केंद्र ने यह भी कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर बातचीत के लिए नई कमेटी का गठन किया जाएगा। सरकार के इस प्रस्ताव के बाद भी किसानों ने कहा कि कानूनों की वापसी के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं। वार्ता शुरू होने के बाद किसानों ने सबसे पहले कानून वापसी की मांग रखी और उसी पर बातचीत करना चाहते थे। करीब ४० मिनट की वार्ता के बाद लंच ब्रेक हुए। इस दौरान किसानों ने कहा कि सरकार उनकी प्रमुख मांगों पर कोई बातचीत नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि लेकर चर्चा शुरू हुई तो केंद्र ने कानूनों का मुद्दा छेड़ दिया। किसान नेताओं ने आंदोलन से जुड़े लोगों को राष्ट्रीय जांच एजेंसी, एनआईए की तरफ से नोटिस भेजने का भी विरोध किया। कृषि कानूनों और किसान आंदोलन पर विचार के लिए बनाई अपनी बनाई कमेटी के सदस्यों पर सवाल उठाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। उसने कहा कि किसी सदस्य पर सिर्फ इसलिए सवाल नहीं उठाया जा सकता कि उसने कानूनों को लेकर अपनी राय जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कमेटी को कोई फैसला करने का अधिकार नहीं है इसलिए पक्षपात का सवाल कहां से उठता है। गौरतलब है कि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने कमेटी के सदस्यों को सरकारी सदस्य बताते हुए उनके साथ मीटिंग करने से इनकार किया है तो एक दूसरे किसान संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर सदस्यों को बदलने का आग्रह किया था। इस याचिका पर विचार करते हुए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा– हमने कमेटी को अधिकार दिया है कि किसानों की बात सुने और हमें रिपोर्ट सौंपे। इसमें भेदभाव की क्या बात है? कोर्ट को बदनाम न करें। कमेटी पर भेदभाव के आरोपों पर अदालत ने कहा– कमेटी के सदस्यों को फैसला लेने का अधिकार नहीं दिया है। अगर आपको कमेटी के सामने नहीं जाना तो मत जाइए लेकिन, इस तरह किसी को बदनाम न करें। सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलन कर रहे किसानों से कहा– आप कमेटी के किसी सदस्य पर सिर्फ इसलिए आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कृषि कानूनों पर राय दी थी। हमने कमेटी में एक्सपर्ट नियुक्त किए हैं, क्योंकि हम इस मामले में एक्सपर्ट नहीं हैं। हमने कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा रखी है। अदालत ने किसानों को कहा कि वे प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन शांति बनी रहनी चाहिए। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई कमेटी गुरुवार को किसानों से मिलेगी। कमेटी के तीन सदस्यों ने मंगलवार को बैठक की थी, जिसमें यह तय किया गया था कि गुरुवार को किसानों से वार्ता होगी और उसके बाद कमेटी सरकार का भी पक्ष जानेगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने चार सदस्यों की कमेटी बनाई थी, जिसके एक सदस्य भूपिंदर सिंह मान ने कमेटी छोड़ दी और कहा कि वे किसानों के साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी ने कहा है कि जो किसान उनके पास आएंगे, उनकी बात सुनी जाएगी और जो नहीं आएंगे, कमेटी के सदस्य उनसे मिलने भी जाएंगे। कमेटी ने अ नलाइन सुझाव लेने के लिए पोर्टल भी बनाया है। इस पर १५ मार्च तक किसानों के सुझाव लिए जाएंगे। सरकार ने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने अपना पक्ष रखेगी। लेकिन आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने कहा है कि वे इसमें शामिल नहीं होंगे। जो किसान संगठन कमेटी बनाए जाने का समर्थन कर रहे थे वे भी कमेटी के सदस्यों की निष्पक्षता को लेकर भरोसे में नहीं हैं।

बाइडेन–हैरिस युग का आगाज

वाशिंगटन। अमेरिका में आधिकारिक रूप से बाइडेन–हैरिस युग की शुरुआत हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप की विदाई और बतौर राष्ट्रपति डमोक्रेटिक पार्टी के नेता जो बाइडेन की शपथ का दुनिया

भर में स्वागत किया गया है। बाइडेन ने भारतीय समय के मुताबिक रात साढ़े १० बजे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। भारतीय मूल की कमला हैरिस ने अमेरिका की पहली महिला उप राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। छह जनवरी को अमेरिकी संसद पर हुए ट्रंप समर्थकों के हमले को देखते हुए राष्ट्रपति के उद्घाटन समारोह में अभूतपूर्व सुरक्षा का बंदोबस्त किया गया था। समारोह की सुरक्षा के लिए २५ हजार नेशनल गार्ड्स तैनात किए गए थे। कई दिन पहले ही पूरे वाशिंगटन डीसी इलाके में इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई थी। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति के रूप में अपना आखिरी दिन व्हाइट हाउस में बिताया। उन्होंने विदाई से पहले अपने करीबी १४३ लोगों को क्षमादान दिया। विदा होने से पहले उन्होंने कहा कि वे अमेरिकी लोगों के लिए काम करते रहेंगे और किसी न किसी रूप में लोगों से फिर उनकी मुलाकात होगी। इससे पहले उन्होंने विदाई भाषण में अपने चार साल के कार्यकाल की तारीफ करते हुए कहा कि बिना किसी युद्ध के उन्होंने राष्ट्रपति का चार साल का कार्यकाल पूरा किया है और यह बड़ी उपलब्धि है। तीन नवंबर को हुए चुनावों के बाद से ही नतीजों को विवादित बनाने का प्रयास कर रहे ट्रंप ने विदाई से पहले नए राष्ट्रपति जो बाइडन को बधाई और शुभकामना भी दी। इसके बाद वे फ्लोरिडा रवाना हो गए। वे राष्ट्रपति बाइडेन के उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं हुए। उनकी छोटी बेटी टिफैनी ने अपने पिता के कार्यकाल के आखिरी दिन राष्ट्रपति भवन में सगाई की। बहरहाल, बतौर राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने कार्यकाल के पहले दिन कई अहम फैसले करने वाले हैं। वे कई मुस्लिम बहुल देशों के लोगों के अमेरिका में प्रवेश पर लगाई गई ट्रंप की पाबंदी को हटाएंगे और साथ ही अमेरिका–मैक्सिको सीमा पर बन रही दीवार के निर्माण पर रोक लगाएंगे। वे शपथ लेने के बाद पेरिस जलवायु समझौते और विश्व्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका को फिर से जोड़ेंगे। बताया जा रहा है कि बाइडेन शपथ लेने के बाद १७ आदेशों पर दस्तखत करेंगे। वे पिछले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले आव्रजन, पर्यावरण, कोविड–१६ के खिलाफ जंग और अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर अलग राह अख्तियार करेंगे। गौरतलब है कि बाइडेन ने अमेरिका के सबसे ज्यादा उम्र के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है तो कमला हैरिस पहली महिला के तौर पर उप राष्ट्रपति बनी हैं।

कांग्रेस ने सुरक्षा समिति पर लगाए आरोप

नई दिल्ली। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने बुधवार को प्रेस बयान जारी करके सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी सीसीएस पर देश की सुरक्षा से जुड़े भेद लीक करने का आरोप लगाया है। बालाकोट एयर स्ट्राइक की खबर तीन दिन पहले ही रिपब्लिक टीवी के प्रमुख अर्णब गोस्वामी को मिलने की खुलासा होने के बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सीसीएस के सदस्यों द्वारा सर्वोच्च रक्षा भेद लीक हुआ, जो देश की सुरक्षा व अखंडता के लिए घातक है। कांग्रेस ने कहा की गोपनीयता कानून और संविधान की शपथ का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जांच हो और उन्हें तुरंत बरखास्त किया जाए। बुधवार को कांग्रेस के दिग्गज नेताओं– पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी, राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद, पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और पूर्व विदेश व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने एक साझा बयान जारी किया, जिसमें अर्णब गोस्वामी के लीक हुए व्हाट्सऐप चौट्स के हवाले केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया। पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी ने कहा कि किसी पत्रकार को तीन दिन पहले ही एयर स्ट्राइक की जानकारी कैसे थी? यह पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि सैन्य अभियान का भेद लीक करना देशद्रोह है। मामले में दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। सरकार को तत्काल मामले में जांच के आदेश देने चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने कहा है– बालाकोट हवाई हमले से तीन दिन पहले २३ फरवरी को इस जर्नलिस्ट को अनधिकृत रूप से न केलक रक्षा मामलों के सबसे गोपनीय भेद पता चल जाते हैं, बल्कि वह इस भेद को सोशल मीडिया पर दूसरे व्यक्ति के साथ साझा भी कर देता है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है– इन भेदों की जानकारी प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को होती है। इन्हीं चार में से कोई यह जानकारी अर्णब गोस्वामी को दे सकता है। इनमें से सभी व्यक्तियों ने देश की सुरक्षा की संवैधानिक शपथ ली है। जाहिर है इनमें से किसी ने संवैधानिक शपथ का उल्लंघन किया है। दूसरी ओर अर्णब की गिरफ्तारी की मांग के संबंध में महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं ने गृह मंत्री अनिल देशमुख से मंगलवार को मुलाकात की। इसके बाद देशमुख ने कहा कि अर्णब की चौट से पता चलता है कि उन्हें बालाकोट स्ट्राइक की पहले से ही जानकारी थी, जबकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा था। उन्होंने कहा– केंद्र सरकार को इस पर नोटिस लेना चाहिए। हम भी इस पर कानूनी सलाह लेंगे। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पीएम मोदी ने यूपी में ६.१० लाख लाभार्थियों को जारी की आवास योजना की किस्त

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक कार्यक्रम के दौरान देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (पीएमएवाई–जी) के ६.१ लाख लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए २,६६१ करोड़ रुपये की रकम जारी की। पीएमएवाई–जी मोदी सरकार की महत्वकांक्षी योजना है जिसके तहत २०२२ तक देश के ग्रामीण इलाके में सबको आवास की सुविधा मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री वीडियो क न्फ्रेंस के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस मौके पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के तहत जारी यह राशि उत्तर प्रदेश के जिन ६.१ लाख लाभार्थियों को मिलेगी उनमें ५.३० लाख ऐसे लाभार्थी होंगे जिन्हें आर्थिक सहायता की पहली किस्त प्राप्त होगी जबकि ८० हजार लाभार्थी ऐसे होंगे जिन्हें दूसरी किस्त मिलेगी और जिन्हें पीएमएवाई–जी के अंतर्गत पहली किस्त पहले ही दी जा चुकी है।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण २० नवंबर, २०१६ को शुरू हुई थी और इस योजना के तहत देशभर में अब तक १.२६ करोड़ घर पहले ही बनाए जा चुके हैं। पीएमएवाई–जी के अंतर्गत मैदानी इलाकों में प्रत्येक लाभार्थी को घर बनाने के लिए १.२० लाख रुपये जबकि पहाड़ी क्षेत्रों (पूर्वोत्तर राज्यों/दुर्गम स्थानोंध्जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित क्षेत्रोंध आईएपी/एलडबल्यूई जिलों) के लोगों को १.३० लाख की आर्थिक सहायता दी जाती है। पीएमएवाई–जी के लाभार्थियों को घर के अलावा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजी एनआरई जीएस) के अंतर्गत अकुशल कामगार श्रेणी के तरह भी मदद दी जाती है। साथ ही शौचालय निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण (एसबीएम–जी), एमजी एनआरई जीएस या अन्य श्रोतों से १२,००० रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना को केंद्र सरकार और राज्यों तथा केंद्र शासित सरकारों की अन्य योजनाओं के साथ भी जोड़ा गया है। इसके तहत लाभार्थी को एलपीजी कनेक्शन का लाभ देने के लिए उज्ज्वला योजना, बिजली कनेक्शन, और सुरक्षित पेयजल आपूर्ति के लिए जल जीवन मिशन इत्यादि को इसमें शामिल किया गया है।

मैं साफ–सुथरा, मोदी से नहीं डरता : राहुल

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान आंदोलन को लेकर मंगलवार को केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि ये तीनों कानून देश की कृषि व्यवस्था को बरबाद करने के

लिए बनाए गए हैं और इनसे तीन–चार पूंजीपतियों का कृषि क्षेत्र पर एकाधिकार हो जाएगा। राहुल गांधी ने केंद्र को निशाना बनाते हुआ यह भी कहा कि वे किसी से डरते नहीं हैं। उन्होंने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के उठाए सवालों पर पलटवार करते हुए कहा कि नड्डा कोई देश के प्रोफेसर नहीं हैं कि उनके हर सवाल का जवाब दिया जाए। राहुल गांधी ने मंगलवार को प्रेस कांफ्रेंस की और कहा– मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं डरता। मैं साफ–सुथरा आदमी हूं। वे मुझे गोली मार सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते। मैं देशभक्त हूं और अपने देश की रक्षा करूंगा। कोई मेरा साथ नहीं देगा तब भी अकेला लड़ता रहूंगा। यह मेरा धर्म है। राहुल ने कृषि कानूनों की कमियां बताने वाली एक बुकलेट भी रिलीज की। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून देश की कृषि व्यवस्था को बरबाद करने के लिए तैयार किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल ने दावा किया कि इन कानूनों से कृषि क्षेत्र पर तीन–चार पूंजीपतियों का एकाधिकार हो जाएगा और खेती की पूरी व्यवस्था आजादी से पहले की हालत में चली जाएगी। उन्होंने किसान संगठनों की तर्ज पर तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग की। राहुल गांधी ने 'खेती का खून' शीर्षक से बुकलेट जारी करते हुए संवाददाताओं से कहा– देश में एक त्रासदी पैदा हो रही है। सरकार इस त्रासदी को नजर अंदाज करना चाहती है और लोगों को गुमराह करना चाहती है। किसानों का संकट इस त्रासदी का एक हिस्सा मात्र है। उन्होंने दावा किया– हवाईअड्डों, बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, दूरसंचार, रिटेल और दूसरे क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर एकाधिकार स्थापित हो गया है। तीन–चार पूंजीपतियों का एकाधिकार है। ये तीन–चार लोग ही प्रधानमंत्री के करीबी हैं और उनकी मदद करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कृषि क्षेत्र अब तक एकाधिकार से अछूता था, लेकिन अब इसे भी निशाना बनाया जा रहा है और ये तीनों कानूनों इसलिए लाए गए हैं। राहुल ने कहा– इससे पहले खेती में एकाधिकार नहीं था। इसका फायदा किसानों, मजदूरों, गरीबों और मध्यम वर्ग को मिलता था। खेती का पूरा ढांचा था जो इनकी रक्षा करता था। इसमें मंडियां, कानूनी व्यवस्था और खाद्य सुरक्षा शामिल थे। अब फिर इस पूरे ढांचे को आजादी से पहले वाली स्थिति की तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है।

पंचायत चुनावों से यह जाहिर हो जाएगा कि हम कितने पानी में

लखनऊ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी प्रदेश के आगामी पंचायत चुनाव के जरिए वर्ष २०२२ में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों का आकलन करके सामने आने वाली कमियों को दूर करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बुधवार को बताया कि उनकी पार्टी आगामी मार्च–अप्रैल में संभावित पंचायत चुनाव को वर्ष २०२२ के शुरू में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी का जायजा लेने के बेहतरीन मौके के तौर पर देख रही है। उन्होंने कहा "पंचायत चुनावों से यह जाहिर हो जाएगा कि हम कितने पानी में हैं और अगले विधानसभा चुनाव के लिए हमें और कितने प्रयास करने होंगे।"लल्लू ने कहा कि ग्रामीण इलाकों तक पहुंच बनाने के लिए पार्टी ने संगठन सृजन अभियान शुरू किया है। इसके तहत अब तक प्रदेश की ६१ फीसदी ग्राम पंचायतों में संगठन तैयार कर लिया गया है। इस माह के अंत तक बाकी ग्राम पंचायतों में भी काम पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों से पार्टी को बहुत उत्साहजनक संकेत मिल रहे हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने तीन नएंषि कानूनों के मामले में भाजपा सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब तक किसानों के हित में ईमानदारी से नीतियां नहीं बनेंगी तब तक उनकी दशा ठीक नहीं की जा सकती।

मोदी ने गुरू गोविंद सिंह को नमन किया

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर उनका नमन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को ट्वीट किया, मैं गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के पवित्र अवसर पर उनका नमन करता हूं। उन्होंने

अपना संपूर्ण जीवन न्यायपूर्ण और समावेशी समाज बनाने के लिए समर्पित किया। वो अपने सिद्धांतो का पालन करने में अटूट थे। हम उनके साहस और बलिदान का भी स्मरण करते है। उन्होंने कहा, गुरु गोविंद सिंह जी के ३५०वें प्रकाश पर्व के मेरी सरकार के कार्यकाल में स्थान लेने के कारण श्री गुरु साहिब की मुझ पर विशेष कृपा रही है। मैं इस अवसर पर पटना में हुए भव्य समारोह का स्मरण करता हूं,जहां मुझे जाने और सत्कार करने का अवसर प्राप्त हुआ।

तीन महीने बाद सामने आए जैक मा

बीजिंग। करीब तीन महीने तक गायब रहने के बाद चीनी अरबपति कारोबारी जैक मा बुधवार को दुनिया के सामने आए। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें जैक देश के करीब एक सौ ग्रामीण शिक्षकों से वर्चुअल मीटिंग करते दिख रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद अलीबाबा के शेयरों में अच्छा–खासा इजाफा हुआ। अलीबाबा समूह के मालिक और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल जैक मा पिछले तीन महीने से लोगों के सामने नहीं आए थे। जैक मा के लापता होने को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं। हालांकि उनके सामने आने के बाद भी कहा जा रहा है कि चीन की सरकार उनकी कंपनी का राष्ट्रीयकरण करने की तैयारी कर रही है। चीन की सरकार, अर्थव्यवस्था और बैंकिंग व्यवस्था की आलोचना करने के कुछ दिन बाद ही जैक मा लापता हो गए थे। उन्होंने पिछले साल अक्टूबर में चीन के वित्तीय नियामकों और सरकारी बैंकों को ब्याजखोर बता कर उनकी तीखी आलोचना की थी। चीन के

राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ भी उनका विवाद हुआ था। इसके बाद से ही वे लापता थे। जैक मा ने चीन सरकार से अपील की थी कि व्यवस्था में ऐसे बदलाव किए जाएं, जो कारोबार में नई चीजें शुरू करने के प्रयास को दबाने की कोशिश न करे। उनके भाषणों चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी नाराज हो गई थी। जैक मा की आलोचना को कम्युनिस्ट पार्टी पर हमले के रूप में लिया गया।

आधे केस अकेले केरल में!

नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस के केसेज की संख्या में तेजी से कमी आ रही है। अब केरल इकलौता राज्य है, जहां संक्रमण काबू में नहीं आ रहा है। इससे पहले केरल इकलौता राज्य था, जिसने संक्रमण की पहली लहर को पूरी तरह से काबू में कर लिया था। लेकिन पिछले साल ओणम का त्योहार मनाए जाने के बाद केरल में संक्रमण बढ़ना शुरू हुआ तो अब तक काबू में नहीं आ रहा है। अब देश में हर दिन आने वाले संक्रमितों की नई संख्या में करीब आधे केस अकेले केरल के होते हैं। बुधवार को देर रात तक देश भर में १४ हजार के करीब नए केसेज आए, जिसमें ६,८९५ यानी करीब आधे केस अकेले केरल के थे। इसके बाद बचे हुए केसेज में करीब आधे नए केस महाराष्ट्र से आ रहे हैं। बुधवार को महाराष्ट्र में कई दिन के बाद तीन हजार से ज्यादा केसेज आए। बुधवार को राज्य में ३,०१५ नए केसेज आए, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या १६ लाख ६७ हजार से ज्यादा हो गई। भारत में एक्टिव केसेज में भी तेजी से कमी आई है। पिछले हफ्ते एक्टिव केसेज घटने की रफ्तार कम हो गई थी पर इस हफ्ते में इसमें तेजी से गिरावट हुई है और यह एक लाख ६० हजार के करीब पहुंच गई है। इसमें अकेले केरल की हिस्सेदारी ४० फीसदी के करीब है। वहां ७० हजार से ज्यादा एक्टिव केसेज हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में ४८ हजार से ज्यादा एक्टिव केस हैं। दोनों में फर्क यह है कि महाराष्ट्र में मृत्यु दर काफी ऊंची रही, जबकि केरल में संक्रमितों की मरने की दर काफी कम रही है। इस बीच बुधवार को देर रात तक भारत में संक्रमितों की कुल संख्या एक करोड़ छह लाख का आंकड़ा पार कर गई। देर रात तक १४ हजार के करीब नए मामले सामने आए थे, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या एक करोड़ छह लाख ११ हजार के करीब पहुंच गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार को २३१ नए मामले आए, जिसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या छह लाख ३२ हजार ८२१ हो गई। पश्चिम बंगाल में ४१२ और उत्तर प्रदेश में ३३४ नए केसेज आए।

ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी में तबाही

नई दिल्ली। भारत में भले कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार कम हो रहा है पर दुनिया के कई देशों में इस वायरस ने अब भी तबाही मचा रखी है। ब्रिटेन में मंगलवार को एक दिन में रिकार्ड संख्या में १६ सौ लोगों की मौत हुई है। वहां मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। उधर फ्रांस में एक दिन में २३ हजार नए मामले आने से हड़कंप मचा है। जर्मनी में केसेज जरूर कुछ कम हुए हैं फिर भी नए संक्रमितों की संख्या बहुत बड़ी है। तभी जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने देश में लागू लॉकडाउन को १४ फरवरी तक बढ़ाने का ऐलान किया है। रूस में भी नए संक्रमितों की रोजाना की औसत संख्या २२ हजार के करीब बनी हुई है। दुनिया भर में संक्रमितों की संख्या नौ करोड़ ६८ लाख के करीब हो गई है। भारतीय समय के मुताबिक बुधवार को रात नौ बजे तक पिछले २४ घंटे में छह लाख से ज्यादा नए मामले आए, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या बढ़ कर नौ करोड़ ६७ लाख ८० हजार से ज्यादा हो गई। जहां तक वायरस के संक्रमण से मरने वालों का सवाल है तो भारतीय समय के मुताबिक बुधवार को रात नौ बजे तक पिछले २४ घंटे में दुनिया भर १७ हजार लोगों की मौत हुई, जिसके बाद मरने वालों का आंकड़ा २० लाख ६६ हजार से ऊपर पहुंच गया। कोरोना वायरस के संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका में लगातार तीसरे दिन संक्रमितों की संख्या दो लाख से नीचे रही। भारतीय समय के मुताबिक बुधवार को रात नौ बजे तक पिछले २४ घंटे में एक लाख ८६ हजार नए मामले सामने आए, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या बढ़ कर दो करोड़ ४८ लाख १८ हजार से ज्यादा हो गई। जहां तक मरने वालों की संख्या का सवाल है तो भारतीय समय के मुताबिक बुधवार को रात नौ बजे तक पिछले २४ घंटे में अमेरिका में २,७७४ लोगों की मौत हुई, जिसके बाद मरने वालों का आंकड़ा चार लाख ११ हजार ६५७ हो गया। अमेरिका और भारत के बाद दुनिया में तीसरे सबसे ज्यादा संक्रमित देश ब्राजील में दो दिन की कमी के बाद बुधवार को संक्रमितों की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ। भारतीय समय के मुताबिक बुधवार को रात नौ बजे पिछले २४ घंटे में ब्राजील में ६३ हजार के करीब नए केसेज आए, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या बढ़ कर ८५ लाख ७५ हजार से ज्यादा हो गई थी। इसी अवधि में ब्राजील में १,१८३ लोगों की मौत हुई, जिसके बाद मरने वालों की संख्या दो लाख ११ हजार ५११ हो गई। दुनिया में चौथे सबसे ज्यादा संक्रमित देश रूस में बुधवार को संक्रमितों की संख्या में लगातार तीसरे दिन कमी आई। बुधवार को रूस में २१,१५२ नए मामले आए, जिसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या ३६ लाख ३३ हजार से ऊपर पहुंच गई। रूस में मरने वालों की संख्या ६७,२२० हो गई है। संक्रमितों के आंकड़े वर्ल्डमीटर्स की वेबसाइट की सूचना पर आधारित हैं।

हावड़ा–कालका मेल का नाम बदलकर रखा गया नेताजी एक्सप्रेस

नई दिल्ली। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की १२५वीं जयंती से पहले रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि हावड़ा–कालका मेल का नाम बदलकर 'नेताजी एक्सप्रेस' कर दिया गया है। गोयल ने ट्वीट करते हुए लिखा, नेताजी के पराक्रम ने भारत को स्वतंत्रता और विकास के एक्सप्रेस मार्ग पर पहुंचा दिया है। मैं 'नेताजी एक्सप्रेस' के साथ उनकी जयंती को मनाने के लिए रोमांचित हूं। जब केंद्र सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया कि हर साल २३ जनवरी को नेताजी की जयंती को 'पराक्रम दिवस' के तौर पर मनाया जाएगा, इसके बाद ही १६ जनवरी को ट्रेन के नाम को बदलने का आदेश पारित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर २३ जनवरी को पश्चिम बंगाल जाने वाले हैं।

व्हाट्सऐप को केंद्र सरकार की चेतावनी

नई दिल्ली। सोशल मैसेजिंग ऐप व्हाट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर केंद्र सरकार ने कंपनी को चेतावनी दी है। सरकार ने कहा है कि कंपनी अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को वापस ले। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि चाहे कोई भी कंपनी हो उसे डाटा की प्राइवेसी की गारंटी करनी होगी। इससे पहले उनके मंत्रालय ने व्हाट्सऐप से कहा है कि ऐप की प्राइवेसी प लिसी में किए गए हालिया बदलावों को वापस लिया जाए। सरकार का कहना है कि किसी भी तरह का एकतरफा बदलाव निष्पक्ष और स्वीकार करने योग्य नहीं है। नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सऐप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ विल कैथकार्ट को सख्त पत्र लिखा है। पत्र में मंत्रालय ने कहा है कि दुनिया भर में भारत में व्हाट्सऐप के सबसे ज्यादा यूजर भारत में हैं। साथ ही

भारत व्हाट्सऐप की सेवाओं का सबसे बड़ा बाजार है। मंत्रालय ने अपने पत्र में लिखा है– व्हाट्सऐप की सेवा शर्तों और प्राइवेसी प लिसी में प्रस्तावित बदलाव से भारतीय नागरिकों की पसंद और स्वायत्तता को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हुई हैं। मंत्रालय ने कहा है कि व्हाट्सऐप को प्रस्तावित बदलावों को वापस लेना चाहिए। साथ ही सूचना की प्राइवेसी, डाटा की सुरक्षा और पसंद की आजादी को लेकर अपने नजरिए पर फिर से विचार करना चाहिए। रविशंकर प्रसाद ने कहा– इस मुद्दे पर मेरा विभाग काम कर रहा है, और निर्णायक प्राधिकारी होने के नाते मेरे लिए इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। लेकिन, एक बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा। चाहें व्हाट्सऐप हो, फेसबुक हो, या कोई भी डिजिटल मंच आप भारत में व्यापार करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन यहां काम कर रहे भारतीयों के अधिकारों का अतिक्रमण किए बिना ऐसा कीजिए।

तेजी से फैल रहा बुलेट का आतंक तेज आवाज से लोगों को परेशानी

लखीमपुर खीरी। जिले की तहसील पलिया कलां में आजकल बुलेट गैंग ने आतंक मचा रखा है। जिससे नगरवासियों समेत सड़को पर आवागमन कर रहे बड़े बुजुर्ग बहू बेटियों में दहसत का माहौल है। जानकारों के अनुसार उक्त बुलेट चालक फायर जैसी तीव्र आवाज निकालते हुए पूरे नगर में दिनभर बेखौफ होकर घूमते है। इनकी बुलेट की तेज आवाज सुनकर सड़क से गुजर रहे राहगीरों की ध ड़कनें तक बढ़ जाती है। नाम न छापने की शर्त पर एक चिकित्सक ने बताया कि फायर जैसे हाई व ल्यूम से हार्ट पेसेंट की मौत हो सकती है। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि इन लोगो की बाइकें जब्त कर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही करें मगर इन पुलिस प्रशासन सुस्त रवैया के कारण के खामियाजा नगर के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। नगर के लोगों ने भी इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखते हुए पुलिस प्रशासन पर तमाम सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं।

नेपाल बार्डर पर किया गया कम्बल वितरण

पलिया कला खीरी। नेपाल की तलहटी दुधवा नेशनल पार्क के जंगलों मैं निबास करने बाली थारू जनजाति मैं एकल अभियान ने कम्बल बितरण किये। एकल अभियान प्रत्येक गांव मे ३ दिवसीय राम कथा का आयोजन कर रहा है इस राम कथा के माध्यम से प्रत्येक गांव ,प्रत्येक घर मैं धर्म का जागरण हो शिक्षा संस्कार स्वावलंबन से वनबासी समाज को देश की मुख्यधारा से जोड़ने के लिय एकल अभियान निरंतर प्रयास रत है। एकल अभियान ३० वर्ष से वनबासी समाज को स्वाभलमवी बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। नेपाल बार्डर पर निवास करने बाली थारू जनजाति के लोगो को बुधवार को कम्बल बितरण किया गया। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए एकल अभियान के भारत नेपाल समन्वयक ओमप्रकाश ने कहा स्वाभलमवी स्वाभीमानी भाव जगाना है चलो गांव की ओर हमे फिर देश बनाना है जब देश की सीमा मैं रहने बाला समाज अपने देश के लिए जागरूक होगा तब ही देश सुरक्षित रह सकता है। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए एस एस बी इंस्पेक्टर रामदेव मिर्धा ने कहा बार्डर पर काम करने वाली सभी संस्थाएं जब उनको सीमा पर निवास करने वाले समाज सहयोग नही करेगा तब तक उनको किसी प्रकार की जानकारियां प्राप्त नही होगी मिर्धा ने कहा वनवासी समाज को किसी भी तरह की कोई जानकारी यदि मिलती है तो बार्डर पर काम करने बाली संस्थाओं को जरूर सूचना दे जिससे देश मे होने बाली किसी भी प्रकार की घटनाओं को रेका जा सके गौरीफंटा कोतवाल रमेश चन्द्र ने कहा पुलिस जनता की मित्र है पुलिस का जब आप सहयोग करेंगे तो सीमा पर किसी भी तरह की अनहोनियों को रोक पाने में सक्षम रहेगी। कार्यक्रम मे समाज सेवी रवि गुप्ता ने कहा वनबासी समाज आज निम्न जींवन जीने पर बिबस है ४७ गांव ७०००० आबादी के बाद भी थारू समाज देश की मुख्यधारा से कटा है रवी ने कहा नेपाल का वार्डर होने के बाद भी न नेटवर्क न शिक्षा की उचित व्यबस्था स्वस्थ्य ले लिए थारू समाज को ११० किलोमीटर दूर जिला केंद्र पर जाना पड़ता है। कार्यक्रम मे संघ के खण्ड कार्यवाह प्रकाश ने आये हुए बनबासी समाज के कंधे से कन्धा मिलाकर एकल अभियं के साथ चलने का आवाहन किया। कार्यक्रम मे १२० लोगो को कम्बल बितरण किया गया। बच्चों को क पी पेन भी दिया गया कार्यक्रम मे डॉ अशोक चौहान, किसन गुप्ता, सूर्यवली वर्मा, पंकज, राम नरेश, राम नरायन बिहारी दास, रामा सरे ,प्रमिला अनीता, संजू, राणा आदि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन श्याम कजरिया ने किया।

डीएम ने किया जिला स्तरीय तीन दिवसीय विज्ञान प्रदर्शनी का शुभारंभ

जीआईसी में आयोजित हुई विज्ञान प्रदर्शनी, जिलेभर के 77 विद्यालयों ने किया प्रतिभाग

लखीमपुर खीरी। बुधवार को समग्र शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश के तहत जिला स्तरीय तीन दिवसीय विज्ञान प्रदर्शनी का शुभारंभ जिला मुख्यालय जीआईसी प्रांगण में हुआ। जिसका शुभारंभ डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने फीता काटकर किया। डीएम ने जिला विद्यालय निरीक्षक ओ.पी. त्रिपाठी व जीआईसी प्रधानाचार्य डॉ आरके आर्य के साथ लगाए गए स्टालों का अवलोकन कर मौजूद छात्र– छात्राओं से उनके प्रोजेक्ट से संबंधित जानकारी ली। उनका उत्साहवर्धन किया। डीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि इन प्रदर्शनी के माध्यम से बच्चों में विज्ञान के प्रति रुझान बढ़ाता है। उनकी सोच में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। बचपन से ही बच्चों को विज्ञान के क्षेत्र में अभिरुचि पैदा करें। ताकि वह आगे चलकर भारत के सुनहरा भविष्य बने। आज के बच्चे कल का भविष्य है। इसलिए उन्हें विज्ञान प्रदर्शनी के माध्यम से विज्ञान के जोड़कर उनका भविष्य संवारे। डीआई ओएस ओपी त्रिपाठी ने विज्ञान प्रदर्शनी की प्रासंगिकता एवं रूपरेखा पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा विभाग इस प्रकार की प्रदर्शनी के आयोजनों से बच्चों की बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता में वृद्धि करेगा। उन्होंने बताया कि इस तीन दिवसीय विज्ञान प्रदर्शनी में जिले के ७७ विद्यालयों द्वारा एक–एक स्टाल लगाए गए। जिसमें ४४ राजकीय विद्यालय, २६ सहायता प्राप्त विद्यालय व ०६ निजी क्षेत्र के विद्यालयों ने प्रतिभाग किया। जिसमें २२० छात्र एवं छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा। विज्ञान प्रदर्शनी में भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान जीव विज्ञान एवं गणित विषय के विशेषज्ञ और विज्ञान प्रदर्शनी के जूरी मेंबर बनाए गए। विजेता प्रतिभागियों को प्रदर्शनी के अंतिम दिन अपराहन १२ बजे सम्मानित किया जाएगा।

तेंदुआ को लेकर अफवाह हुई सच साबित

लखनऊ। तेंदुआ को लेकर अफवाह सच साबित हो गई है। बंथरा क्षेत्र में दो तेंदुआ शिकार की तलाश में घूम रहे हैं। यहां राष्ट्रीय वनास्पति संस्थान परिसर (एनबीआरआइ) में दो तेंदुआ होने की पुष्टि हो गई है। दोनों ही व्यस्क है। वन विभाग ने तेंदुआ होने की सूचना पर ट्रैकिंग की थी। करीब सात मीटर जमीन के हिस्से को साफ करने के बाद उसमे मिट्टी व बालू की लेयर बनाई गई थी। एनबीआरआइ परिसर में पांच जगह ट्रैकिंग की गई थी, जिसमे से दो जगह तेंदुआ के पगमार्क मिले हैं। अब तेंदुआ को पकडने के लिए वन विभाग की टीम सक्रिय हो गई है। जगह–जगह पिंजड़ा लगाकर उसमे मुर्गा और बकरा बांधा गया है।अभी तक मलिहाबाद क्षेत्र में तेंदुआ होने की सूचना थी, लेकिन अगले दिन तेंदुआ की कोई लोकेशन न मिलने से यह माना जा रहा था कि वह जंगल के रास्ते बाहर निकल गया था लेकिन एक सप्ताह पहले बंथरा में तेंदुआ होने की सूचना पर वन विभाग ने लकड़बग्घा बताया था। इस दौरान (एनबीआरआइ) के अधिकारियों ने परिसर में किसी जंगली वन्यजीव होने की सूचना दी थी। वन विभाग की टीम ने पांच दिन पहले ही परिसर में ट्रैकिंग कराई थी। दो दिन पहले बालू व मिट्टी की लेयर में दो अलग–अलग पगमार्क मिले थे। जिसकी स्केल में जांच की गई तो तेंदुआ होने की पुष्टि हुई। डीएफओ डा. आरके सिंह ने बताया कि बंथरा में एनबीआरआइ परिसर में दो तेंदुआ होने की पुष्टि हो गई है। दोनों के पगमार्क पाए गए। पगमार्क से साफ है कि दोनो तेंदुआ व्यस्क हैं। परिसर में कई जगह ट्रैकिंग के लिए जमीन को समतल करने के साथ ही वहां पर बालू और मिट्टी की लेयर बनाई गई है। इस लेयर से अगर तेंदुआ गुजरेगा तो पगमार्क बन जाएगा। उसे पकडने के लिए पिंजड़े लगाए गए हैं। यह वन्यजीव रात में ही अपना शिकार करने के साथ ही यात्रा भी तय करता है। दिन भर जंगल व झाडियों में छिपा रहता है।गोमती नदी के किनारे माल और बक्शी का तालाब सीमा के कठवारा जंगल के आसपास तेंदुआ होने की सूचना पहले से ही है। कठवारा गांव में आबादी भी है और मवेशी भी रहते हैं। गोमती नदी के कछार और कठवारा जंगल में उसके भोजन पानी का ठीक–ठाक इंतजाम होने से वह आबादी के बीच नहीं आ रहा था और माना जा रहा है कि यही तेंदुआ शहर के विभिन्न ग्रामीण इलाकों से होकर बंथरा पहुंचा है।

लखनऊ पुलिस ने मुंबई कमिश्नरेट को सौंपे अभिलेख

लखनऊ। तांडव वेब सीरीज के निर्माता और निर्देशक के खिलाफ कार्रवाई के लिए लखनऊ पुलिस ने मुंबई में डेरा डाला है। पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही है। हालांकि अभी तक किसी भी

आरोपित से पूछताछ नहीं कर सकी है। लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में तैनात इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम मुंबई गई है। लखनऊ पुलिस ने बुधवार को सबसे पहले डीसीपी ठाणे कार्यालय में जाकर मामले की जानकारी दी। हालांकि इस दौरान वहां डीसीपी मौजूद नहीं मिले।इसके बाद पुलिस टीम मुंबई कमिश्नर के दफ्तर पहुंची और प्रकरण के बारे में बताया। इसके साथ ही एफआइआर से संबंधित अभिलेख भी उपलब्ध कराए। लखनऊ पुलिस ने कहा कि हजरतगंज कोतवाली में तांडव वेब सीरीज के निर्माता, निर्देशक, लेखक समेत अन्य के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काने समेत अन्य धाराओं में एफआइआर दर्ज है। इसी संबंध में पुलिस टीम आरोपितों से पूछताछ और उनके बयान दर्ज करने के साथ ही अग्रिम कार्रवाई के लिए मुंबई आई है। हजरतगंज कोतवाली में तांडव वेब सीरीज के खिलाफ एफआइआर दर्ज होने और पुलिस टीम के मुंबई पहुंचने की जानकारी मिलने पर पुलिस के पास लगातार फोन आ रहे हैं। एक पुलिस अधिकारी ने बुधवार को बताया कि वेब सीरीज में दिखाए गए दृश्य से आहत लोग महाराष्ट्र समेत अलग–अलग राज्यों से फोन कर पुलिस टीम की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर मुंबई में लखनऊ पुलिस को अगर किसी प्रकार की समस्या आए तो वह उनकी मदद करने को तैयार हैं। गौरतलब है कि सोमवार देर रात में वेब सीरीज तांडव के निर्देशक अली अब्बास, निर्माता हिमांशु कृष्ण मेहरा, लेखक गौरव सोलंकी और हेड इंडिया ओरिजिनल कंटेंट अमेजन के अपर्णा पुरोहित के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में एफआइआर दर्ज की गई थी।

पुजारी की सिर कूचकर निर्मम हत्या

लखनऊ। बख्शी का तालाब में एक तीर्थस्थल पर देर रात वहां रहने वाले पुजारी की निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या करने वालों ने देवस्थल के घंटे, दानपत्र की रकम तेल और अनाज भी लूट ले गये। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल कर

रही है। घटनास्थल पर एसपी ग्रामीण ह्यदेश कुमार,सीओ डॉ ह्यदेश कठेरिया पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया गया है।बीकेटी थाना क्षेत्र में शिवपुरी रोड पर पुजारी की हत्या की वारदात रणबाबा तीर्थस्थल पर हुई। तीर्थस्थल पर रहने वाला पुजारी फकीरेदास सुल्तानपुर जिले का रहने वाला बताया जाता है। शिवपुरी के ग्रामीणों के मुताबिक देवस्थान पर पुजारी १५ वर्षो से रहते थे। एक वर्ष बीच में कहीं चले गये थे फिर वापस आकर रहने लगे। शिवपुरी निवासी कामता ने बताया पुर गांव का रहने वाला एक बाबा भी रहता था कठवारा गांव का बल्लेबाबा भी रहता था। पुजारी से पुर अक्सर झगड़ा होता था।घटना के पीछे लूटपाट की बात सामने आ रही है। घटनास्थल पर पुजारी के पास रखे दानपात्र टूटा पड़ा था और उसमें से रुपये गायब मिले। परिसर में बने कमरे से अनाज तेल भी गायब मिले। पुजारी के सिर पर ईंट से कूंचने की वजह से गहरे चोट के निशान मिले हैं।ग्रामीणों के मुताबिक देवस्थल पर लगे पेड़ पर करीब ढाई कुंतल तक घंटे घंटिया बंधी थी जो सुबह गायब मिले। आंशका जताई जा रही लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों पुजारी के सिर पर ईंट मारकर हत्या कर दी। पुजारी के शव के पास पड़ी ईंट के टुकड़े में खून लगा मिला। पुजारी के पास ११५ रुपये भी पड़े मिले। घटना स्थल पर फोरेंसिक टीम और डाग स्क्वायड की टीम द्वारा जांच की गई। एसपी ग्रामीण ने बताया घटनास्थल को देखा गया पुजारी के सिर पर चोट के निशान हैं। घटना के संबंध में कुछ अहम सुराग मिले हैं। एसपी ने लूटपाट की घटना से इन्कार किया है।बीकेटी थाना क्षेत्र के रणबाबा देव स्थल की कुटी पर देर रात पुजारी फकीरे दास की निर्मम हत्या का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले बीकेटी थाना क्षेत्र के बराखेमपुर गांव से कुछ दूरी पर स्थित अकोहरा बाबा देव स्थल पर बीते वर्ष १० फरवरी को वह के पुजारी अमरनाथ तिवारी की धारदार हथियार से गला काटकर नृशंस हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद कुछ दिनों तक जांच पड़ताल होती रही और पुलिस हत्यारों का पता लगाने का प्रयास करती रही। घटना का १ वर्ष बीत जाने के बावजूद पुजारी हत्याकांड का पुलिस खुलासा नहीं कर सकी है।

छात्राओं का वाट्सएप ग्रुप हैककर डर्टी ग्रुप पर डाले नंबर

लखनऊ। एक शातिर युवक ने एक इंटर कलेज की छात्राओं का वाट्सएप ग्रुप हैक कर लिया। इसके बाद वाट्सएप ग्रुप के सभी मोबाइल नंबर सोशल मीडिया के डर्टी ग्रुप पर डाल दिया। इसके बाद छात्राओं

के पास अभद्र और अश्लीलता भरे फोन आने लगे। छात्रा के पिता की तहरीर पर इंस्पेक्टर गौतमपल्ली आलोक कुमार राय ने आरोपित सौरभ सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर आलोक कुमार राय ने बताया कि करीब १५ दिन दिन पहले सौरभ ने क्षेत्र स्थित एक इंटर कॉलेज की छात्राओं का वाट्सएप ग्रुप हैक किया था। उसमें करीब १८ से १६ नंबर थे। आरोप है कि सौरभ ने सारे नंबर डर्टी ग्रुप पर डाल दिए। स्कूल खुलने के बाद वह विद्यालय के गेट के आस आकर खड़ा होता था और छात्राओं का पीछा करते हुए छींटाकशी करता था। बीते दिनों एक छात्रा ने इसकी शिकायत अपने पिता से की। इसके बाद पिता ने तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। आरोपित सौरभ सिंह पवनपुरी तेलीबाग के देवीखेड़ा का रहने वाला है। वाट्सएप पर अभद्र मैसेज आने पर छात्रा ने जब सौरभ को फोन कर विरोध किया और उसके बारे में जानकारी करने की कोशिश की तो वह उसे धमकाने लगा। मुकदमा दर्ज होने के बाद साइबर और सर्विलांस सेल को भी लगाया गया। आरोपित की लोकेशन ट्रेस की गई। लोकेशन के आधार पर उसे बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया।

संगठन सृजन अभियान के तहत न्याय पंचायत स्तर पर किया गठन

कृष्ण कुमार शुक्ला

पलियाकलां–खीरी। पलिया विधानसभा में संगठन सृजन अभियान के तहत न्याय पंचायत का गठन किया गया। आपको बता दें कि पलिया विधानसभा में संगठन सृजन अभियान महासचिव उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधायक अजय कुमार लल्लू के दिशा निर्देशन से ब्ल क अध्यक्ष सचिन शाह के नेतृत्व में पलिया ब्ल क की न्याय पंचायत बनकटी एवं न्याय पंचायत सिंगहिया में साथी कांग्रेसजनों के साथ सभा करके न्याय पंचायत का गठन कराया। साथ ही ग्राम पंचायत सेड़ा बेड़ा, ग्राम पंचायत बनकटी, ग्राम पंचायत सूंडा एवं ग्राम पंचायत कजरिया में जनता से मिल कर कांग्रेस पार्टी की नीतियों को समझाया। इस दौरान थारू क्षेत्र के लोगों ने कांग्रेस जनों को हाथों हाथ लिया व कांग्रेस पार्टी से जुड़ने की इच्छा जताई। बताते हुए प्रसन्नता होती है कि अब थारू क्षेत्र की जनता मौजूदा भा ज पा की केंद्र सरकार से ऊब चुकी है व कांग्रेस पार्टी की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। इस दौरान ब्ल क अध्यक्ष के साथ पलिया नगर अध्यक्ष आबिद हुसैन खां, ब्ल क उपाध्यक्ष पूर्व प्रधान रामचन्द्र सिंह, आदिल खान, संदीप गौतम, आसाराम, रामचंदर बन्दर्भरारी, बाबूराम, महाराज,राममिलन ,दरबारी ,रामू, सिद्धू, बदला ,जय बहादुर ,राम फकीर, राजेश कुमार, कन्हैया लाल, बंधु राम नंदू राम ,लबरा, शालिग्राम, भजनलाल, परसराम ,नारायण ,बबलू आदि दर्जनो कांग्रेसजन मौजूद रहे।

गरीब की जिंदगी बदलने की प्रधानमंत्री की सोच ले रही है मूर्त रूप : योगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए गरीब की जिंदगी में बदलाव लाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच मूर्त रूप ले रही है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत उत्तर प्रदेश के ६१०००० लाभार्थियों के खाते में २६६०.७७ करोड़ रुपए की धनराशि के डिजिटल अंतरण के अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश के हर गरीब, किसान, मजदूर, महिला, नौजवानों को केन्द्र तथा राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है इस

कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वर्चुअल माध्यम से शिरकत की।योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ने हर गरीब के आवास के सपने को साकार किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के आवास देश और प्रदेश के हर गांव में निर्मित हो रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में भी प्रधानमंत्री आवास योजना (नगरीय) के आवास बनाये जा रहे हैं। इस योजना के माध्यम से गरीब के जीवन में परिवर्तन की प्रधानमंत्री जी की सोच मूर्तरूप ले रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक अप्रैल २०१६ को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की घोषणा की थी और उसी साल २० नवम्बर को प्रदेश के आगरा से यह योजना शुरू हुई। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत राज्य में अब तक १४ लाख ६१ हजार गरीब परिवारों को आवास दिये गये हैं। इनमें से १४ लाख ३३ हजार आवास पूर्ण हो गये हैं। योगी ने कहा कि वर्ष २०२०–२१ के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत स्वींत आवासों में से एक लाख ७६ हजार आवासों के लाभार्थियों को पहली किस्त दी जा चुकी है। आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा ५.३० लाख आवासों के लाभार्थियों को पहली किस्त तथा ८० हजार लाभार्थियों को दूसरी किस्त प्रदान की जा रही है। इस तरह आज ६.१० लाख लाभार्थियों को २६६० करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि उनके खातों में दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अभियान चलाकर केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

बॉलीवुड में डेब्यू करेंगी श्रीदेवी–बोनी कपूर की बेटी खुशी कपूर

मुंबई। बॉलीवुड की दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी और फिल्मकार बोनी कपूर की छोटी बेटी खुशी कपूर बॉलीवुड में जल्द ही डेब्यू कर सकती हैं। बोनी कपूर और श्रीदेवी की बेटी जान्हवी कपूर ने पूछा गया तब उन्होंने कहा कि हां, खुशी भी ऐक्टिंग करना चाहती हैं और आप जल्द ही कोई अनाउंसमेंट सुन सकते हैं। बोनी कपूर ने स्पष्ट किया है कि वह उन्हें लॉन्च नहीं कर रहे। बोनी

बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत कर ली है। अब श्रीदेवी–बोनी कपूर की छोटी बेटी खुशी कपूर के बॉलीवुड में एंट्री को लेकर चर्चा हो रही है। खुशी पहले से ही सोशल मीडिया पर काफी ऐक्टिव हैं। खुशी बहुत जल्द बॉलीवुड में कदम रखने जा रही हैं। बोनी कपूर से जब इस बारे में कपूर ने बताया कि वह खुशी को लॉन्च नहीं कर रहे। उन्होंने कहा, मेरे पास रिसोर्सेस हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इन्हें कोई और लॉन्च करे, वर्ना पक्षपात वाला रवैया आ जाता है। आप बतौर फिल्ममेकर इसे अफोर्ड नहीं कर सकते और न ही एक ऐक्टर के लिए यह अच्छा है।

नगर के लोगों ने मंदिर निर्माण के लिए दान

पलियाकलां–खीरी। श्रीराम मंदिर निर्माण समर्पण अभियान के अंतर्गत आज राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जिला सेवा प्रमुख बलजीत सिंह कुशल नेतृत्व में बाला जी ज्वेलर्स के प्रोपाइटर संदीप गुप्ता ने अपनी अर्धांगनी (समाज सेविका) श्रीमती संदीपा गुप्ता के साथ संयुक्त रूप से ३११०१ रुपये मंदिर निर्माण हेतु स्वेच्छिक दान किया है इसी क्रम में नगर के राम भक्त पूर्व चेयरमैन केबी गुप्ता, ५,१००, जीवन प्रकाश मैनरो ११०००, गगन मिश्रा ५,१००, घनश्याम दिवाकर११०००, सुरेश चंद्र गर्ग ५,१०० ,शुशील गुप्ता ने ५,१०० राषि का दान किया है उक्त पुनीत कार्य में हिन्दू युवा वाहिनी के व्लाक कोषाध्यक्ष नीरज मौर्य, पालकधजिला संपर्क प्रमुख कृष्ण अवतार भाटी का सक्रिय योगदान रहा है।

ईद पर रिलीज होगी सलमान की राधे

मुंबई। बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान की फिल्म 'राधे : योर मोस्ट वॉन्टेड भाई' इस वर्ष ईद के अवसर पर रिलीज होगी। वर्ष २०२० में कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के चलते वित्तीय समस्याओं को समझ सकता हूं जिनसे थिएटर मालिकध एग्जिबिटर्स गुजर रहे हैं और मैं राधे को थिएटर्स में रिलीज कर उनकी मदद करना चाहता हूं। इसके बदले में, मैं उनसे उम्मीद

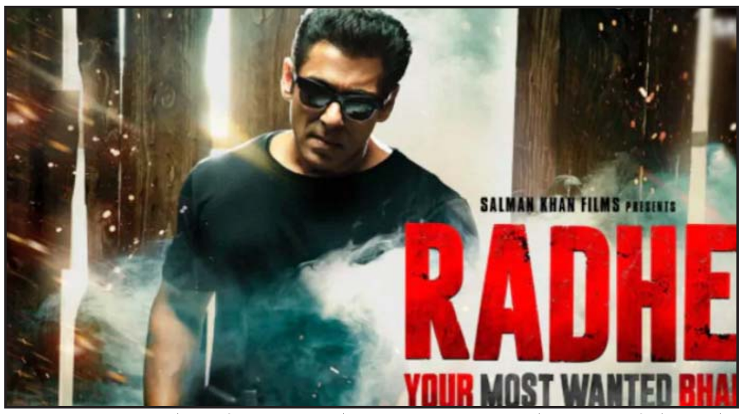

बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई बड़ी फिल्मों की शूटिंग और रिलीज पर ब्रेक लग गया था। अब साल २०२१ में एक बार फिर इंडस्ट्री धीरे–धीरे रफ्तार पकड़ रही है। सलमान खान ने अपनी 'राधेः योर मोस्ट वॉन्टेड भाई' के ईद के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होने घोषणा की है। सलमान ने यह जानकारी सोशल मीडिया पर एक नोट शेयर कर फैन्स को दी है। सलमान खान ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक नोट शेयर किया है, जिसमें लिखा है, "माफ करें मुझे सभी थिएटर मालिकों को वापस जवाब देने में लंबा समय लग गया। इस समय यह एक बड़ा निर्णय है। मैं उनकी करता हूं कि वे थिएटर्स में 'राधे' देखने के लिए आने वाले दर्शकों के लिए सेफ्टी का पूरी तरह ध्यान रखेंगे। वादा ईद का था और यह इंशाल्लाह २०२१ की ईद पर ही रिलीज होगी। सिनेमाघरों में राधे का आनंद लें।" गौरतलब है कि वर्ष २०२० में कोरोना वायरल के चलते लॉकडाउन के कारण फिल्म राधे की शूटिंग पूरी नहीं हो पाई थी। लॉकडाउन खत्म होने के बाद सलमान और दिशा ने शूट खत्म किया था। फिल्म का निर्देशन प्रभू देवा ने किया है। इसमें सलमान और दिशा पाटनी के अलावा जैकी श्रॉफ, रणदीप हुड्डा जैसे सितारे भी नजर आएंगे।

कंगना रनौत के ट्विटर हैंडल पर लगा अस्थायी प्रतिबंध

मुंबई। अभिनेत्री कंगना रनौत ने आज ट्वीट किया कि उनका ट्विटर अकाउंट अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। मगर, मेरा री–लोडेड देशभक्त संस्करण मेरी फिल्मों के जरिए बार–बार आता रहेगा। तुम्हारा जीना दुश्वार करके रहूंगी।

प्रतिबंध कंगना के वेब सीरीज 'तांडव' पर बयान देने के बाद लगाया गया है। अभिनेत्री ने ट्वीट किया, लिबरल अब उनके चाचा जैक के पास जाकर रोने लगे और मेरे अकाउंट को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कराया। वे लोग मुझे ध मका रहे हैं। मेरा अकाउंटध वर्चुअल आइडेंटिटी कभी भी देश के लिए शहीद हो सकती है। 'तांडव' का कई लोगों ने विरोध किया है। उन्होंने इस वेब सीरीज पर सांप्रदायिक भेदभाव के लिए उकसाने और हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है। शिकायतों के अनुसार, एक दृश्य में जीशान अय्यूब एक कॉलेज प्ले के दौरान हिंदू देवता शिव का अपमान करते नजर आ रहे हैं।

हमारे अन्य प्रतिनिधि
lat; ckt ibZ
lhrkiqj
eks-9935160370
प्रियंका त्रिपाठी
नई दिल्ली
विधिक सलाहकार
lqj'k ukjk;.k feJ
क्षेत्रीय सम्पादक
lkjHk dqekj] fcgkj
eks-09386075289
मो० अरशद
C;qjks phQ
eऊ

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय द्वारा सांई आफसेट प्रिन्टर्स, 40 वासुदेव भवन भातखण्डे संगीत महाविद्यालय के पीछे, कैसरबाग लखनऊ से छपवाकर एमआईजी 2/379 रश्मिखंड शारदानगर आशियाना लखनऊ उ0प्र0 से प्रकाशित।
आर.एन.आई UPHIN/2010/32566

सम्पादक
आरती पाण्डेय
मो.9415087228
9889745884. 9807059191. 9026560178
Email- adbhutsamachar@yahoo.in
adbhut_samachar@rediffmail.com
सभी विवादों का न्यायक्षेत्र लखनऊ होगा।

समाचार पत्र में छपी समस्त प्रकार की खबरों एवं लेखों का स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। समाचार पत्र में छपी खबर एवं लेख पत्रकारों के अपने निजी विचार हैं। समाचार पत्र से जुड़े समस्त पत्रकारों के पद अवैतनिक हैं। और वह सब स्वतंत्र पत्रकार हैं। प्रकाशक/सम्पादक